Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
5 अक्तूबर 2017

पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने की जारी मुहिम की संगठन ने की निंदा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने कुछ मीडिया के द्वारा चलाई जा रही संगठन को बदनाम करने की मुहिम की कड़ी निंदा की और उन्हें चैलेंज करते हुए कहा कि वे अपने आरोप साबित करने के लिए साफ साफ सबूत पेश करें। मीडिया राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक रिपोर्ट का हवाला देती है, जिसमें लगभग हिंदुत्व संगठनों, विशेष रूप से आरएसएस के द्वारा तैयार किये गए झूटे प्रोपगंडे को ही एक बार फिर से दोहराया गया है। एनआईए के हवाले से मीडिया ने जिन मामलों की लिस्ट बयान की है वे बिल्कुल ही बेवज़न हैं और संगठन के तौर पर पॉपुलर फ्रंट का उनसे कोई संबंध नहीं है। बैठक ने इस दुष्ट प्रोपगंडे के खिलाफ कानूनी तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया है।

एक दूसरे प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने एनआईए की रिपोर्ट पर अपनी चिंता और गुस्से का इज़हार करते हुए एजेंसी से देश को अपनी निष्पक्षता व गैर जानिबदारी का यकीन दिलाने की बात कही है। पहले ही यह देखा गया है कि एनआईए मालेगांव, अजमेर, समझौता और मक्का मस्जिद आदि जैसे कई एक आतंकवाद से जुड़े मामलों में, जिनमें हिंदुत्व समूह लिप्त पाए गए हैं, नरमी से काम ले रही है। उनमें से अधिकतर मामलों में आरोपी पाए गए लोगों की ज़मानत की याचिका पर एनआईए ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं वरिष्ठ सरकारी वकील ने खुद यह आरोप लगाया है कि कोर्ट के सामने नरमी बरतने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। यह बात भी शक से खाली नहीं कि एनआईए विशेष मामलों की जाँच करने के बजाय अपने दायरे से बाहर जा रही है और खास तौर से मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार एजेंसी हिंदुत्व समूहों के राजनीतिक एजेंडे को मज़बूती दे रही है। एनआईए के नाम से आई हालिया रिपोर्टों ने एजेंसी की साख को और भी नीचे गिरा दिया है।

बैठक ने यह विचार भी व्यक्त किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का केंद्र सरकार का निर्णय मानवता के खिलाफ है। यह मौलिक मानवाधिकार और शरणार्थियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह फैसला अत्याचार और हिंसा से बचकर भागने वाले लोगों को शरण देने की हमरी लम्बी परम्परा के भी खिलाफ है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार

40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा के लिए खतरा समझती है, जो म्यांमार सरकार के रवैये का समर्थन करने जैसी बात है। बैठक ने सभी संगठनों और मानवाधिकार समूहों से देश में मौजूद बेसहारा रोहिंग्या शरणार्थियों को हर संभव मदद देने और सरकार पर अपनी पॉलीसी में बदलाव लाने के लिए दबाव डालने की अपील की।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों, ज़ोन के अध्यक्षों और एनईसी के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली